

भारत सरकार
वित्तमंत्रालय
वित्तीयसेवाएं विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्नसंख्या *5

(जसिका उत्तर 15 दसिम्बर, 2017/24 अग्रहायण, 1939 (शक) को दिया जाना है)

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्यबीमा योजना

*5. डॉ. उदति राज:

क्या वित्तमंत्रियह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 से 2010 के दौरान तीन वर्षोंके लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्यबीमा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख शिल्पिकारों के बीमा के लिए 190 करोड़ रुपए की राशिका भुगतान किया है और यदहिं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधिकरण ने पाया है कि एक बीमा कंपनी द्वारा फर्जी और अपात्र लाभार्थियोंका बीमा किया गया है और इस कारण उनसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है, यदहिं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) चहिनति किए गए ऐसे लाभार्थियोंकी संख्या सहति फर्जी या अपात्र लाभार्थियोंकी कुल संख्या का पता लगाने के लिए भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधिकरणद्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या बीमा अधनियिम, 1938 की धारा 33 के अधीन इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और यदहिं, तो इस संबंध में की गई कार्रवाईसहति तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्तमंत्रि(श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'राजीव गांधी शलिपी स्वास्थ्यबीमा योजना' के संबंध में डॉ. उदति राज द्वारा पूछे गए 15 दसिम्बर, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्नसंख्या *5 के भाग (क) से (घ) के उत्तरमें उल्लिखित विवरण।

(क): वस्त्रमंत्रालयकी राजीव गांधी शलिपी स्वास्थ्यबीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) के अंतर्गत वर्ष-वारजारी की गई नधियां नमिनानुसार हैं:-

		(करोड़ रुपए में)	(लाख में)
क्रमसं.	वर्ष	स्वीकृत नधियां	नामांकित शलिपिकारों की संख्या
1.	2007-08	67.84	8.82
2.	2008-09	79.46	10.11
3.	2009-10	67.55	8.03
	कुल	214.85	26.95

(ख) और (ग): भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार, वस्त्रमंत्रालयकी राजीव गांधी शलिपी स्वास्थ्यबीमा योजना के अंतर्गत अपात लाभार्थियों से संबंधित एक शकियत थी।

आईआरडीएआई ने 6-7 मई, 2013 को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड(बीमाकर्ता) का नरीक्षणकिया था तथा मामले की वसितृत जांच की थी। प्राधिकरणद्वारा यह पाया गया था कि 11,445 खादी बुनकर की नविल प्रीमियमराशि 10.3 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज के साथ, जो कुल 1.18 करोड़ रुपए थी, बीमाकर्ताद्वारा वस्त्रमंत्रालयको वापस कर दी गई थी। यह पाया गया था कि योजना में उक्त 11,445 सदस्य खादी बुनकर थे जिन्हें बीमाकर्ता के अनुसार श्रेणीकरणसंबंधी चूक के कारण शामिल किया गया था। चूंकि खादी बुनकर को शलिपिकार की इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शलिपिकार नहीं माना जा सकता, इसलिए बीमाकर्ताने उक्त राशि वस्त्रमंत्रालयको वापस कर दी।

(घ): इसके अलावा, आईआरडीएआई ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ज) के अंतर्गत गहन नरीक्षणकिया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आरजीएसएसबीवाई के मामले में आरोप शामिल थे। नरीक्षणके दौरान की गई टपिणियों के आधार पर तथा बीमाकर्ताद्वारा किए गए नविदन की जांच करने के पश्चात आईआरडीएआई ने 31 मार्च 2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नरिधारित वनियामकीय उपबंधों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्डके वरिद्ध 10 लाख रुपए का दण्ड लगाते हुए 03 सतिम्बर, 2015 को अंतिम आदेश जारी किया गया था।
